

प्रदेश में स्थापति किये जाएंगे 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2023 को प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में महिलाओं के वरिद्ध अपराध, जैसे- बलात्कार, छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिये 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापति करने का नरिणय लया गया है।

प्रमुख बढि

- प्रत्येक ज़िला जहाँ उपरोक्त वर्णति श्रेणियों के 50 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं, वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापति करने का नरिणय लया गया है।
- प्रदेश के फरीदाबाद में दो तथा गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत तथा नूह ज़िला में 1-1 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापति की जाएगी।
- हरयाणा पुलिस अकादमी में महिला जाँच अधिकारियों के लयि नयिमति तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा रफ़्रेशर कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि वे न केवल कानूनी प्रावधानों में हुए नए संशोधनों के बारे में अपडेटेड रहे, बल्कि मामले की प्रभावी तथा समयबद्ध तरीके से जाँच कर सकें।
- सीन ऑफ़ क्राइम टीम द्वारा घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के लयि सभी ज़िलों में जाँच अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन कटि उपलब्ध करवाई गई है। यह इन्वेस्टिगेशन कटि वैज्ञानिक तरीके से काफी उच्चतर है, जसिसे जाँच प्रक्रया को और अधिक नषिपक्ष बनाया जा सकता है।
- महिला सुरक्षा की डीआईजी नाजनीन भसीन ने बताया कि महिला वरिद्ध अपराधों की मॉनटरिंग को लेकर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नयिक्त कया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- आपराधिक कानून संशोधन-2018 के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार होने पर मामले की जाँच 2 महीने की समयवधि में पूरे कयि जाने का प्रावधान कया गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम मृत्यु दंड का प्रावधान कया गया है।



॥



